



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235 ]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 30, 2001/भाद्र 8, 1923

No. 235]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2001/BHADRA 8, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महाविशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2001

विषय : संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए सफेद सीमेंट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच—अन्तिम निष्कर्ष

सं. 64/1/2000-डीजीएडी.— 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

## क. कार्य-पद्धति

2. जांच के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनाई गई है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को नियमावली के अधीन घरेलू उद्योग की ओर से मै0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि0 तथा मै0 जै के सिंथेटिक्स लि0 से लिखित याचिका प्राप्त हुई है जिसमें यूएई तथा ईरान (जिसे इसके बाद सम्बद्ध देश कहा

गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए सफेद सीमेंट (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है;

- (ii) प्राधिकारी ने उक्त नियम-5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए पाटन संबंधी निवेदन के प्राप्त होने की सूचना भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को दी;
- (iii) प्राधिकारी ने अपने समक्ष उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच आरम्भ करने का निर्णय लिया ।
- (iv) प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 6 दिसम्बर, 2000 की सावर्जनिक सूचना जारी की गई जो सम्बद्ध देशों से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के शीर्ष 2523.21 के अन्तर्गत आने वाली सम्बद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच आरम्भ करने के बारे में थी,
- (v) प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के बारे में दिनांक 22.2.2001 की अधिसूचना द्वारा प्रारम्भिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया और हितबद्ध पक्षों से अपने विचार लिखित रूप में इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर देने का अनुरोध किया;
- (vi) प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्षों की एक प्रति ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को भेजी और उनसे प्रारम्भिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार यदि कोई हो, इसके प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर देने का अनुरोध किया,

- (vii) प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्षों की एक प्रति संबंध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को इस अनुरोध के साथ भिजवाई कि वे अपने देशों के निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों को उपरोक्त ( v ) और (vi) में बताई गई समय-सीमा के अन्दर प्रारम्भिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार देने की सलाह दें ;
- (viii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों को 11.4.2001 को अपने विचार मौखिक रूप से देने का अवसर प्रदान किया । विचार व्यक्त करने वाली सभी पार्टियों को अपने विचार लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । पार्टियों को विपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियाँ प्राप्त करने और उनका खण्डन, यदि कोई हो भिजवाने की सलाह दी गई ;
- (ix) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली फाइल सार्वजनिक फाइल के रूप में सभी हितबद्ध पार्टियों को उनके अनुरोध पर उपलब्ध कराई ;
- (x) प्रारम्भिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए जिन तर्कों को अधिसूचित किए गए प्रारम्भिक निष्कर्षों में शामिल किया गया है, उन्हें संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । तथापि, हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में उठाए गए तर्कों पर इन निष्कर्षों में उचित स्थान पर विचार किया गया है,
- (xi) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधार का खुलासा सभी ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है,
- (xii) जॉच में शामिल अवधि 1 जनवरी, 1999 से 30 जून, 2000 है,

(xiii) इस अधिसूचना में ... किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमों के अधीन उसे वैसा ही माना है;

(ख) याधिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार और प्राधिकारी द्वारा उनकी जाँच

3. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रारम्भिक निष्कर्षों में और प्रकटन विवरण पत्र में भी चर्चा की गई है। जिन विचारों पर प्रारम्भिक निष्कर्षों में और प्रकटन विवरण-पत्र में पहले विचार नहीं किया गया है और जो मुद्दे अब प्रकटन विवरण में जवाब में उठाए गए हैं, उन पर नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार किया गया है जहाँ तक वे नियमानुसार संगत हैं और जहाँ तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं। हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्कों की जाँच की गई और जहाँ कहीं उचित समझा गया है, नीचे संगत पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ईरान के निर्यातकों द्वारा निर्धारित फार्म और विधि में कोई उत्तर नहीं दिए जाने और उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर जाँच परिणाम तैयार करने की पुष्टि करते हैं। आयातकों में से कुछ ने, जैसेकि मै0 श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स, मै0 अक्षयलक्ष्मी ट्रेडिंग प्रा0 लि0, मै0 राजहंश डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा0 लि0, मै0 इंडियन स्मॉल स्केल पेन्ट्स एसोसिएशन आदि ने अभ्यावेदन दिए हैं, जिन पर प्राधिकारी ने विचार किया है।

(ग) विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुएं

4. विचाराधीन उत्पाद "सफेद पोर्टलैंड सीमेन्ट" है जिसे आमतौर पर "सफेद सीमेन्ट" कहा जाता है। यह एक निर्माण सामग्री है और इसका उपयोग गैर-ढाँचागत प्रयोजनों में किया जाता है। जैसे कि टाइलों के फर्श बनाने, सीमेंट आधारित बाहरी भागों, पेन्ट्स और सीमेंट वार्निश इत्यादि में। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 25 के उप-शीर्ष सं0 2523.21 के अन्तर्गत आता है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

नियम 2(घ) की परिभाषा के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं की "समान वस्तुएं" हैं।

#### (घ) घरेलू उद्योग

5. संबद्ध वस्तुओं के भारत में 3 उत्पादक हैं अर्थात् ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेके सिन्थेटिक्स लिमिटेड और द्रावनकोट सीमेंट्स, कोट्टायम। यह याचिका मै0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज और मै0 सिन्थेटिक्स लि0 द्वारा दायर की गई है जोकि कुल घरेलू उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन करते हैं और इस प्रकार वे याचिका दायर करने की स्थिति में हैं। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को बाद में भेजे गए पत्राचार में मै0 द्रावनकोर सीमेंट्स लिमिटेड ने भी पाटनरोधी जाँच का समर्थन किया है।

#### (ङ.) न्यूनतम से कम मात्रा

6. विरोधी हितबद्ध पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी कार्यवाही केवल तभी शुरू की जा सकती है जब किसी खास देश से आयात स्थानीय रूप से विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के 3% से अधिक होता है और इसलिए संयुक्त अरब अमीरात के विरुद्ध जाँच को समाप्त किया जाना चाहिए।

7. पाटनरोधी नियमों के नियम 14(घ) के अनुसार जाँच को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब किसी खास देश से वास्तविक या संभावित पाटित आयातों की मात्रा "समान उत्पाद" के आयातों के 3% से कम होती है। यह न्यूनतम सीमा आयात की कुल मात्रा के संदर्भ में है न कि घरेलू विनिर्मित उत्पाद की मात्रा के संदर्भ में। चूँकि यूएई से आयात भारत में सफेद सीमेंट के कुल आयातों का 3% से अधिक है इसलिए पाटनरोधी जाँच को न्यूनतम मात्रा के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है।

#### च. पाटन

8. सामान्य मूल्य:- जैसाकि प्रारंभिक जाँच परिणामों में उल्लेख किया गया है निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी। तथापि, ईरान के किसी भी निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं भेजा है। इस प्रकार ईरान के निर्यातकों ने इस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करने के विकल्प को अपनाया है। इस प्रकार

नियम 6(8) का पालन किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्यवाही करना पूर्णतः न्यायोचित है ।

अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि ईरान के किसी भी निर्यातक ने नियमानुसार प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है । घरेलू उद्योग ने उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर ईरान में सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है । ईरान के निर्यातकों की ओर से असहयोग को देखते हुए प्राधिकारी ने उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर ईरान में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जैसाकि प्रारंभिक निष्कर्षों में किया गया था ।

9. प्रारंभिक निष्कर्षों और प्रकटन विवरण में यह उल्लेख किया गया था कि मै0 रासअल खैमा कं0 फॉर व्हाइट सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स, यूएई ने पूरी सूचना प्रस्तुत की थी । तथापि, बाद में कंपनी ने उत्पादन लागत, घरेलू बिक्रियों पर प्राप्त लाभ तथा भारत और अन्य देशों को किए गए निर्यात, घरेलू बिक्रियों के लिए बिक्री कीमत संरचना तथा भारत और अन्य देशों को किए गए निर्यात के बारे में ब्यौरे तथा समुद्री भाड़े इत्यादि के बारे में ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं । इसके अलावा कंपनी ने प्राधिकारी को कीमत बचनपत्र प्रस्तुत किया है और घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उसे इस कीमत बचनपत्र को स्वीकार करने और नियम 15 में किए गए प्रावधान के अनुसार इस कंपनी के संबंध में जांच को स्थगित करने पर कोई आपत्ति नहीं है । प्राधिकारी ने प्रस्तुत सूचना स्वीकार की है । इसके अलावा प्राधिकारी ने प्रस्तुत की गई सूचना का मिलान करने के बाद यूएई के सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के उद्देश्य से मै0 रासअल खैमा कंपनी द्वारा उपलब्ध सूचना का उपयोग करने का निर्णय लिया है ।

10. **निर्यात कीमत :** जैसाकि प्रारंभिक निष्कर्षों में उल्लेख किया गया है मै0 रासअल खैमा कं0, फॉर व्हाइट सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स, यूएई ने जांच अवधि के दौरान भारत को हुए उनके निर्यातों के बारे में सूचना प्रस्तुत की थी । बाद में उन्होंने भारत को किए गए निर्यातों पर

समुद्री भाड़े, टर्मिनल हैंडलिंग और स्वदेशी भाड़े जैसे दावा किए गए समायोजनों के संबंध में सूचना भी प्रस्तुत की है। जैसाकि प्रारंभिक निष्कर्षों में उल्लेख किया गया है, ईरान के मामले में निर्यात की मात्रा और कीमत के संबंध में डीजीसीआईएस के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर समायोजन करने के बाद निवल निर्यात कीमत निकाली गई है।

11. **पाटन मार्जिन:** चूंकि ईरान के किसी भी निर्यातक ने सूचना हेतु प्राधिकारी के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने उपरोक्तानुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के प्रयोजनार्थ उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विचार किया है और भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत निर्यात कीमत के साथ की है। इस तुलना से ईरान के लिए पाटन-मार्जिन निवल निर्यात कीमत के 115 % का पता चलता है। यूएई के मामले में ऊपर निकाले गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना की गई है और यह निवल निर्यात कीमत का 52 % बैठता है।

#### **छ, क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

12. अंतिम निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने क्षति से संबंधित सभी संकेतकों को ध्यान में रखा है। इसमें सभी संगत तत्व अर्थात् पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू उद्योग में कीमत पर उनका प्रभाव तथा घरेलू उत्पादकों, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति इत्यादि पर उसके परिवर्त्ती प्रभार शामिल होते हैं। घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तु हेतु क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार किया है जिसमें मानकीकृत खपत संबंधी सर्वोत्तम मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है और जांच अवधि के

दौरान उस कच्ची सामग्री की वास्तविक कीमत को ध्यान में रखा जाता है जिसका इस्तेमाल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा क्षति मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उचित बिक्री अथवा क्षति रहित कीमत निकालने के लिए इष्टतम क्षमता उपयोग को ध्यान में रखा है।

13. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित मापदण्डों से संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का पता चलता है :-

- ( i ) संबद्ध देशों से निर्यात की कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है ;
- ( ii ) जांच अवधि के दौरान आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य खासकर तटवर्ती क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे इन क्षेत्रों में भारी कीमत कटौती की जा रही है ;
- ( iii ) जांच अवधि के दौरान आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की दुलाई लागत सहित उत्पादन लागत से काफी कम था जिससे भारतीय बाजार के तटवर्ती क्षेत्रों में कीमत ह्रास/कमी हो रही है ;
- ( iv ) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी आई है ;
- ( v ) तटवर्ती क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री मात्रा में आई गिरावट के अलावा जांच अवधि के दौरान बिक्री में अधिक गिरावट आई थी। जांच के तत्काल बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में वास्तविक रूप से गिरावट आई है।

14. **क्षति का खतरा:** प्रारंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी ने पाटित आयातों में बढ़ोत्तरी की उच्च वृद्धि दर के कारण घरेलू उद्योग को हो रहे क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग द्वारा की गई कीमत कटौती और संबद्ध देशों में उपलब्ध देशी निपटान क्षमता तथा भंडार सूचियों के ब्यों पर विचार किया था।



पाटित आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभाव के मुद्दे की भी जांच की गई थी । प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जैसाकि उपरोक्त कारको से पता चलता है और यह भी कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को संचयी रूप से क्षति पहुंचने का गंभीर खतरा है ।

15. **कारणात्मक संबंध:** प्रारंभिक निष्कर्षों में यह उल्लेख किया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय बाजारों में पाटित कीमतों पर संवर्धित पाटित आयात के कारण ही घरेलू उद्योग अपनी कीमतें उस स्तर तक कम करने के लिए बाध्य हुआ है जो क्षति रहित कीमत और इन क्षेत्रों में दुलाई लागत को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है, यह निर्धारित किया गया था कि घरेलू उद्योग को उक्त क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है । प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन तथा जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है और यह भी कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आगे और क्षति होने का खतरा है ।

**ज. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे:**

16. कुछेक आयातकों और उपयोक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाते समय संबद्ध वस्तु के औद्योगिक उपयोक्ताओं के हित को ध्यान में रखना चाहिए । उन्होंने संबद्ध वस्तु का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि आयातों का खतरा स्थानीय उत्पादकों की कीमतों पर नियंत्रण के रूप में काम करता है ।

17. इस संदर्भ में प्राधिकारी अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के पैराग्राफ 29 और 30 को दोहराते हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि " पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है और भारतीय बाजार में एक ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल करना है जो देश के सामान्य हित में है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से व्हाइट सीमेंट के इस्तेमाल से विनिर्मित उत्पादों की कीमत रतार प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है । तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लगाने से यूएई और ईरान से होने वाले आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी । उपभोक्ता अब भी आपूर्ति के दो या इससे अधिक स्रोत रख सकते हैं ।

18. स्पष्ट तौर पर पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में व्हाइट सीमेंट के उपभोक्ताओं/उपयोक्ताओं पर अंततोगत्वा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसकी बजाए घरेलू उद्योग की स्थिति मजबूत होगी और भारत में उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रह सकेंगे । पाटनरोधी शुल्क लगाने का एकमात्र उद्देश्य भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिसमें घरेलू उत्पादक और विदेशी उत्पादक दोनों प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे ।

### अन्तिम निष्कर्ष

19. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:-

( i ) व्हाइट सीमेंट का यूएई एवं ईरान से भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है ।

( ii ) भारतीय उद्योग को क्षति हुई है और इसे और अधिक क्षति होने का खतरा है ।

( iii ) यह क्षति संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है ।

20. **कीमत संबंधी वचन-पत्र** : - मै0 रास अल खैमा कं0 फॉर व्हाइट सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैटीरियल, यूएई ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को कीमत संबंधी एक वचन-पत्र दिया है और इस बात पर सहमत हुआ है कि वह व्हाइट पोर्टलैण्ड सीमेंट अथवा व्हाइट सीमेंट की बिक्री सीमाशुल्क शीर्ष सं0 2523.21 के तहत भारतीय पत्तन पर 100 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन की सीआईएफ कीमत से कम कीमत पर नहीं करेगा । उक्त वचन-पत्र में उल्लिखित भारतीय पत्तन हैं : - चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन मुम्बई तथा कांडला । वचन-पत्र में उल्लिखित इन बिक्रियों के भुगतान की शर्तें भी लदान बिल की तारीख से 30 दिनों में भुगतान योग्य साख पत्र (एलसी)के द्वारा हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि संदर्भ सीआईएफ कीमत से जांच अवधि के दौरान कंपनी से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर पाटन से होने वाला क्षति संबंधी प्रभाव समाप्त हो जाएगा । प्राधिकारी कीमत संबंधी इस वचन-पत्र को स्वीकार करते हैं और इसलिए पाटनरोधी शुल्क की लेवी की सिफारिश नहीं करते हैं और मै0 रास अल खैमा कं0 फॉर व्हाइट सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैटीरियल, यूएई के खिलाफ चल रही जांच को बंद करते हैं ।

तथापि, वचन-पत्र के किसी उल्लंघन, जैसे डिस्काउंट सहित वास्तविक बिक्री कीमत, ऊपर उल्लिखित बिक्री कीमत से कम होने की दशा में अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कीमत संबंधी वचन-पत्र को अस्वीकार कर दिए जाने की दशा में प्राधिकारी केन्द्र सरकार को वर्तमान जांच के दौरान उपलब्ध सूचना अथवा उचित स्रोतों से प्राधिकारी की जानकारी में लाई गई सूचना के आधार पर लागू पाटनरोधी शुल्कों की लेवी की उचित सिफारिश करेंगे । प्राधिकारी स्वतः ही अथवा निर्यातक/घरेलू उद्योग या विचाराधीन वस्तु के आयातक या किसी अन्य हितबद्ध पार्टी के किसी अनुरोध के आधार पर इस वचन पत्र के जारी रहने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा कर सकते हैं । इस प्रकार के पाटनरोधी शुल्कों को कीमत संबंधी वचनपत्र के उल्लंघन अथवा वापसी की तारीख से पूर्व-तिथि से लागू किया जा सकता है । केन्द्र सरकार द्वारा कीमत संबंधी वचन-पत्र को स्वीकार नहीं किए जाने की दशा में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की राशि तथा इसकी लेवी की प्रभावी तारीख के बारे में केन्द्र सरकार को अलग से सूचित करेंगे । कीमत संबंधी वचन पत्र की वैधता की अवधि इस संबंध में केन्द्र सरकार की अधिसूचना द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की अवधि के साथ-साथ चलेगी और यह पाटनरोधी नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार समीक्षा के अधीन रहेगी ।

21. प्राधिकारी यह प्रस्ताव करते हैं कि पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जाए जिसे यदि लगाया जाए तो इससे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षतिरहित बिक्री कीमत से की गई है । इस उद्देश्य के लिए आयातों के पहुंच मूल्य का निर्धारण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3,

3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क शामिल करते हुए सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित निर्धारण योग्य मूल्य के रूप में किया गया है।

22. प्राधिकारी यूएई तथा ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित व्हाइट सीमेंट, जो सीमाशुल्क कोड 2523.21 के अंतर्गत आता है, के आयातों पर नीचे यथा निर्धारित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं और मै0 रास अल खैमा कं0 फॉर व्हाइट सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैटीरियल, यूएई द्वारा दिए गए कीमत संबंधी वधन-पत्र, जैसा कि ऊपर पैरा 20 में उल्लिखित है, को स्वीकार करने की भी सिफारिश करते हैं। पाटनरोधी शुल्क निम्नानुसार होगा:-

देश/निर्यातक	सिफारिश किया गया पाटनरोधी शुल्क (अमरीकी डालर प्रति मी0 टन)
1. यूएई (मै0 रास अल खैमा कं0 फॉर व्हाइट सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैटीरियल को छोड़ कर सभी निर्यातक)	32
2. ईरान (सभी निर्यातक)	38

23. उपरोक्त बातों के तहत प्राधिकारी दिनांक 22 फरवरी, 2001 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

24. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th August, 2001

**Subject : Anti-Dumping Investigation concerning imports of White Cement originating in or exported from the UAE and Iran—Final Findings.**

No. 64/1/2000-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

**A. PROCEDURE:**

2. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:-

- (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Grasim Industries Limited and M/s JK Synthetics Ltd., on behalf of the domestic industry, alleging dumping of White Cement(hereinafter referred to as subject goods)

originating in and exported from the UAE and Iran(hereinafter referred to as subject countries);

- (ii) The Authority notified the Embassies of subject countries in India about the receipt of petition made by the petitioners before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub rule(5) of Rule 5 supra;
- (iii) The Authority on the basis of information and evidence available before it decided to initiate anti dumping investigations against imports of subject goods from the subject countries;
- (iv) The Authority issued a Public Notice dated the 6<sup>th</sup> December, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping investigations concerning imports of subject goods from subject country, falling under heading 2523.21 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975;
- (v) The Authority notified preliminary findings vide notification dated 22.2.2001 on anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- (vi) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish

their views, if any, on the preliminary findings within forty days from the date of its publication;

- (vii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassies of subject countries in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (v) and (vi) above.
- (viii) The Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally on 11.4.2001. All parties presenting views were requested to file written submissions of their views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;
- (ix) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request;
- (x) Arguments made by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in these findings;



- (xi) In accordance with Rule 16 of the Rules *supra*, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;
- (xii) The investigation covered the period from 1<sup>st</sup> January, 1999 to 30<sup>th</sup> June, 2000.
- (xiii) \*\*\*\*\* in this notification represents information furnished by the interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

**B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY.**

3. The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the preliminary findings and disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paragraphs herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paragraphs herein below. The Authority confirms, the absence of any response from the exporters from Iran in the form and manner prescribed and having made the findings on the basis of the

best information available to it as per rule 6(8) supra. Some of the importers such as M/s Sree Lakshmi Traders, M/s Akashayalakshmi Trading Pvt. Ltd., M/s Rajhans Distributors Pvt. Ltd., M/s Indian Small Scale Paints Association, etc., have made submissions which have been considered by the Authority.

**C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

4. The product under consideration is “white portland cement” which is normally referred to as “white cement”. It is a construction material and used for non structural purposes such as flooring of tiles, cement based exteriors, paints and cement varnish etc. This falls within Chapter 25 of the Custom Tariff Act under the sub-heading 2523.21. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation. The goods manufactured by the domestic industry are ‘like articles’ to the goods imported from subject countries within the meaning of Rule 2(d).

**D. DOMESTIC INDUSTRY:**

5. There are 3 producers of the subject goods in India, viz., Grasim Industries Limited; JK Synthetics Limited and Travancore Cements Limited, Kottayam. The petition has been filed by M/s. Grasim Industries Ltd., and M/s. JK Synthetics Ltd., who account for more than 90 per cent of total domestic production and thus have the standing to file the petition. However, in the subsequent communication addressed

to Designated Authority, M/s. Travancore Cements Ltd., has also supported the anti dumping investigation.

**E. DEMINIMIS VOLUME:**

6. It has been argued by the opposing interested parties that the anti dumping proceedings can be initiated only if import from one particular country is more than three per cent of the locally manufactured product under consideration and hence the investigation against UAE should be terminated.

7. As per Rule 14(d) of the Anti Dumping Rules, the investigations is to be terminated only if the volume of dumped imports, actual or potential, from a particular country accounts for less than three per cent of the imports of the 'like product'. The de minimus limit is with respect to total volume of import and not with respect to the volume of locally manufactured product. As imports from UAE account for more than 3 per cent of the total imports of white cement into India, the anti dumping investigation cannot be terminated on the grounds of de minimis volume.

**F. DUMPING**

8. **Normal Value :** As brought out in the preliminary findings, the Designated Authority sent questionnaires to known exporters of the subject goods in subject countries. However, none of the exporters from Iran have responded to the Designated Authority. Thus the exporters from Iran have preferred non cooperation with the Designated Authority in this case. Thus Rule 6(8) is attracted and the Designated Authority is

fully justified in proceeding with the best information available. The Authority, therefore, holds that none of the exporters from Iran have cooperated with the Authority as envisaged under the Rules. The domestic industry has furnished information with regard to the normal value in Iran based on the constructed cost of production. In view of non-cooperation from the exporters from Iran, the Authority has determined normal value in Iran on the basis of the constructed cost of production as was done in the preliminary findings.

9. In the preliminary findings, as well as in the Disclosure Statement, it was stated that M/s Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials, UAE, had furnished incomplete information. However, subsequently, the company has furnished details regarding cost of production, profit on the domestic sales and export to India and other countries, sales price structure for domestic sales and export to India and other countries and details regarding ocean freight, etc.. Also the company has given a price undertaking to the Authority and the domestic industry also has stated that they do not have any objection to acceptance of this price undertaking and suspension of investigation in respect of this company as provided under Rule 15. The Authority has accepted the information submitted. Also, the Authority has decided to use the information provided by M/s Ras Al Khaimah Co. for the purpose of calculation of normal value for all the exporters from UAE after reconciling the information submitted.

10. **Export Price:** As stated in the preliminary findings, M/s Ras Al Khaimah Co., for White Cement & Construction Materials, UAE, had furnished the information regarding their exports to India during the period of investigation. Also, subsequently, they have furnished information regarding adjustments claimed on exports to India such as Inland freight, terminal handling and ocean freight. As stated in the preliminary findings, in the case of Iran, the DGCIS data regarding the volume and price of export has been used and after making the adjustments on the basis of information furnished by the domestic industry, the net export price has been worked out.

11. **Dumping Margin:** Since none of the exporters from Iran has responded to the Authority's request for information, the Authority took into account the best information available for the purpose of fair comparison between the normal value and the export price as stated above and compared weighted average normal value with weighted average export price. The comparison shows dumping margin of 115% of net export price for Iran. In the case of UAE, on the basis of the normal value and export price worked out above, the dumping margin has been calculated and it comes to 52 % of net export price.

#### **G. INJURY AND CAUSAL LINK**

12. The Authority has taken into account all indices regarding injury while doing the final determination. This involves all relevant facts viz., volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market

and its subsequent effect on domestic producers, production, capacity utilisation, profitability, net sales realisation etc. While determining the non-injurious price for the like article for the domestic industry, the Authority has considered the optimum cost of production for the domestic industry which takes into account the normated best consumption norms and takes into account the actual price of the raw materials during the POI which go into the production of the product under consideration. Also, while arriving at the injury margin, the Designated Authority takes into account optimum capacity utilisation for arriving at a fair selling or non-injurious price.

13. On the basis of the evidence available, the following parameters show existence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject countries :-

- (i) Export price from subject countries has declined significantly;
- (ii) The landed value of the imported material during the period of investigation is significantly below the selling prices of the domestic industry, especially in the coastal regions causing severe price undercutting in these regions,
- (iii) The landed value of the imported material during the period of investigation was significantly below the cost of production including transportation cost of the domestic industry

causing price suppression/depression in the coastal regions of Indian market;

- (iv) Profitability of the domestic industry has been eroded.
- (v) Apart from the decline in the actual sales volume of domestic industry in the coastal regions, there was potential decline in sales during the period of investigation. The sale of the domestic industry actually declined during the period immediately after investigation.

14. **THREAT OF INJURY:** In the preliminary findings, the Authority had gone in details of the threat of injury being suffered by the domestic industry on account of significant rate of increase of dumped imports, price undercutting suffered by domestic industry and surplus disposable capacity and inventories available in the subject countries. Also question of volume and price effect of the dumped imports was examined. Authority confirms its earlier findings that domestic industry has suffered material injury as evidenced by factors mentioned above and also that there is a serious threat of injury being caused to the domestic industry on account of dumped imports of subject goods from subject countries cumulatively.

15. **CAUSAL LINK :** In the preliminary findings it was stated that taking into account the factor that it is the increased dumped import at dumped prices in localized markets which has forced the domestic industry to reduce its prices to the levels not sufficient to recover the non-injurious price and the transportation cost to these areas, it was determined that the injury to the domestic industry was caused by dumped imports. The Authority confirms its earlier findings that there is a causal link between the dumping of subject goods from subject countries and the injury being caused to the domestic industry during the period of investigation and also threat of further injury being faced by domestic industry on account of dumped imports of subject goods from subject countries.

**G. INTEREST OF INDIAN INDUSTRY AND OTHER ISSUES**

16. It has been argued by some of the importers and users that the interest of the industrial users of subject goods should be taken into account while imposing anti dumping duty. They have requested to reconsider the imposition of anti dumping duty on subject goods since the threat of imports serves as a check on the prices of the local producers.

17. In this context the Authority reiterates paragraphs 29 and 30 of its preliminary findings wherein it is stated that "the purpose of anti



dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using white cement and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from UAE and Iran in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply".

18. Evidently, imposition of anti dumping duty would not adversely affect the consumers/users of White Cement in India in the long run. It would rather lead to survival of domestic industry and keep wider choice to the consumers in India. The very purpose of the imposition of anti dumping duty is to create situation of fair competition in the Indian market in which both domestic producers and foreign producers can

compete. Imposition of anti dumping duty would not lead to restriction on imports.

#### **H. FINAL FINDINGS**

19. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that :

- (i) White Cement has been exported to India from UAE & Iran below its normal value
- (ii) The Indian industry has suffered injury and is facing threat of more injury.
- (iii) The injury has been caused by the dumped imports from subject countries;

20. **PRICE UNDERTAKING** :- M/s Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials, UAE, has given a price undertaking to the Designated Authority and have agreed not to sell White Portland Cement or White Cement under Custom Heading 2523.21 at price CIF Indian Ports below US \$ 100 per MT. The Indian ports mentioned in the undertaking are Chennai, Tuticorin, Cochin, Mumbai and Kandla. Also the payment terms for these sales mentioned in the undertaking are by LC payable 30 days from date of Bill of Lading. The Authority notes that the reference CIF price would eliminate the injurious effect of dumping on the domestic industry caused by imports from the company during the period of investigation. The authority accepts the price undertaking and therefore, does not recommend the levy of anti dumping duty and

suspends investigation against M/s Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials, UAE.

However, in the event of any violation of the undertaking such as actual sale price, net of discounts being lower than that mentioned above or in the event of non-acceptance of price undertaking by the Central Government, the Designated Authority would make appropriate recommendations to the Central Government for levy of applicable anti-dumping duties on the basis of the information as available during the present investigation or as brought to the notice of the authority from appropriate sources. The authority may also suo-moto or on the basis of any request from exporters/domestic industry or importer of the article in question or any other interested parties review from time to time the need for continuance of the undertaking so given. Such Anti-Dumping duties may apply retrospectively from the date of violation or withdrawal of price undertaking. Also in the event of Central Government not accepting the price undertaking, the Designated Authority shall separately intimate the Central Government the amount of Anti-Dumping duty and the effective date of its levy. The validity of the price undertaking would be co-terminus with the duration of the Anti-Dumping duties to be imposed by the Notification of the Central Government in this regard, and shall be subject to review as per the applicable provisions of the Anti-Dumping Rules.

21. The Authority proposes to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is compared with the non injurious selling price of the petitioner companies determined for the period of investigation. Landed value of imports for the purpose has been determined as the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

22. The Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty as set out below on imports of white cement falling under customs code 2523.21 originating in or exported from UAE and Iran and also recommends acceptance of the price undertaking offered by M/s Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials, UAE as mentioned in para 20 above. The anti dumping shall be as follows :-

Country/exporters	Anti dumping duty recommended (US \$ per MT)
1. UAE (all exporters excluding M/s Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials)	32
2. Iran (all exporters)	38

23. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 22nd February, 2001.

24. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, *supra*.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

